Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

आईसीडब्ल्यूए अतिथि खंड

मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन का भारत दौरा

राजदूत स्कंद आर तायाल

27 अप्रैल 2016

10 - 11 अप्रैल 2016 को मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम (एवाईएजी) नई दिल्ली की एक छोटे और व्यवसायिक यात्रा पर आए। यह एवाईएजी की भारत की तीसरी यात्रा थी। पहली यात्रा जनवरी 2014 में हुई थी और यह महत्वपूर्ण यात्रा थी; क्योंकि राजनीतिक उठा-पटक और विवादास्पद चुनाव के नतीजे में पदभार संभालने के बाद एवाईएजी की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी। मई 2014 में एवाईएजी ने दूसरी बार यात्रा की, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य सार्क नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था।

मालदीव हिंद महासागर में लक्षद्वीप के 185 द्वीपों पर फैले लगभग 350,000 आबादी वाला एक छोटा-सा देश है। भारत के लिए यह काफी सुरक्षा और रणनीतिक हित वाला देश है; क्योंकि इसके द्वीप हिंद महासागर में समुद्री गलियों से सटे हैं।

भारत ऐतिहासिक रूप से मालदीव की सरकार और लोगों का मित्र, शुभचिंतक और विशुद्ध सुरक्षा प्रदाता रहा है। मालदीव ने 1965 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। पिछले साल भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50 वीं वर्षगांठ दोनों देशों ने मनाया। पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम ने तीस साल (1978-2008) तक मजबूत पकड़ के साथ देश पर शासन किया और अभी भी उनके विस्तारित परिवार और न्यायपालिका, सेना और आंतरिक सुरक्षा तंत्र में नियुक्तियों के माध्यम से उनका काफी प्रभाव है। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति उनके सौतेले भाई हैं। भारत ने हस्तक्षेप किया और तख्तापलट की कोशिश, जिसका मास्टरमाइंड किराए के श्रीलंकाई तमिल थे, को नाकाम किया। 1988 में एक बार फिर से राष्ट्रपति गयूम की वापसी हुई।

देश में पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में एक उदार, युवा और लोकप्रिय नेता मोहम्मद नशीद को 2008 में राष्ट्रपति चुना गया था। वास्तविक लोकतंत्र को लागू करने के उनके प्रयासों का पुराने मजबूत प्रतिष्ठान द्वारा विरोध किया गया था और 2012 में एक न्यायिक तख्तापलट कर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। तब से आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक विपक्ष की गिरफ्तारी और प्रेस पर नियंत्रण से देश घिर गया है। 2013 में पूर्व राष्ट्रपति नशीद को संदिग्ध आरोपों में 13 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। मोहम्मद नशीद इस समय चिकित्सा आधार पर पैरोल पर हैं और इंग्लैंड में उनका इलाज चल रहा है।

नशीद के शासनकाल ने एक उदार लोकतांत्रिक अभिविन्यास किया था और भारत के समर्थन में इनका झुकाव स्पष्ट था। न्यायपालिका और राष्ट्र के अन्य अंगों में निष्पक्षता और जवाबदेही का परिचय देने का उनका प्रयास उनके पतन का कारण बना। जबकि मोहम्मद नशीद के नेतृत्व वाली मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी परिवर्तन की ताकतों का प्रतिनिधित्व करती है, मालदीव पीपुल्स पार्टी की स्थापना और सशस्त्र बलों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।

एक अंतराल और दो राष्ट्रपति चुनावों के बाद अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम आखिरकार मोहम्मद नशीद को हराने में कामयाब रहे और 2014 की शुरुआत में सत्ता संभाली। हालांकि शुरू में नए

शासन का रुख भारत विरोधी था। इसने खुले तौर पर चीन का साथ दिया और माले हवाई अड्डे के उन्नयन और संचालन के लिए भारतीय कंपनी जीएमआर को दिए गए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक बड़ा ठेका रद्द कर दिया। यह ठेका हाल ही में एक चीनी कंपनी को दिया गया है। इसके अलावा मालदीव के पास एक द्वीप का पट्टा चीन को देने के प्रस्ताव हैं और भारत के आपत्तियों की अनदेखी करते हुए मालदीव समुद्री रेशम मार्ग में चीन का एक उत्साही भागीदार बना है।

भारत और मालदीव के बीच संबंध 2012 से ही असहज थे और मालदीव एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है, जिसका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के रास्ते में सितंबर 2014 में मालदीव और श्रीलंका गए थे।

दिल्ली में रहते हुए एवाईएजी ने अपनी असहज मेजबानों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। प्रेस के साथ बातचीत में उन्होंने घोषणा की कि मालदीव की विदेश नीति में 'इंडिया फर्स्ट' है। उन्होंने यह भी कहा कि मालदीव हमेशा भारत की सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखेगा। उन्होंने कोस्टगार्ड के लिए लंगर और जहाज के लिए गोदी सुविधाएं देने के लिए उथुरु थिला फाल्हू परियोजना में भारतीय भागीदारी को दोहराया। उन्होंने भारत को महत्वाकांक्षी "आईहैवन एकीकृत विकास परियोजना" में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसे मुख्यतया चीनी निवेश के साथ एक प्रमुख ट्रांस-शिपमेंट और लॉजिस्टिक हब के रूप में तैयार किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी के साथ 11 अप्रैल को संयुक्त प्रेस सम्मेलन में मालदीव के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्रियल एक्शन ग्रुप (सीएमएजी) की आगामी समीक्षा बैठक में भारत का समर्थन प्राप्त करना था, जिसे कुछ ही दिनों बाद 20 अप्रैल को आयोजित होना था; ताकि मालदीव प्रशासन पर राष्ट्रमंडल द्वारा कोई दंडात्मक प्रतिबंध न लगाया जाए। राष्ट्रपति यामीन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि, "हम मालदीव पर सीएमएजी द्वारा किसी भी अनुचित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को रोकने में निरंतर समर्थन के लिए भारत की ओर देखते हैं ..... अपेक्षाकृत छोटे देशों को गलत तरीके से दंडित किया जाता है।"

संदिग्ध संसदीय चुनावों की सफलता के बाद राष्ट्रपति के पदभार संभालने के साथ उथल-पुथल और लोकतांत्रिक विपक्ष का दमन और राजनीतिक नेताओं की विवादास्पद गिरफ्तारी को देखते हुए कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्रियल एक्शन ग्रुप मालद्आीप की स्थिति पर विचार कर रहा है।

3 सदस्यीय सीएमएजी मिशन, जिसमें विदेश सचिव एस जयशंकर भी शामिल थे, ने 6-8 फरवरी 2016 को मालदीव का दौरा किया था और मिशन की रिपोर्ट पर 24 फरवरी 2016 को समूह ने विचार किया। निष्कर्ष रिपोर्ट में मिशन ने मालदीव पर कोई दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव करने से परहेज किया और "समावेशी राष्ट्रीय राजनीतिक वार्ता के लिए मालदीव सरकार द्वारा सीएमएजी को दी गई प्रतिबद्धता" का स्वागत किया। हालांकि रिपोर्ट में महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण स्पष्ट था और इसमें कहा गया था: -

“…. देश में नजरबंदी और हिरासत में लिये जाने वाली दोनों घटनाओं तरह की को देखते हुए विपक्ष के लिए उपलब्ध राजनीतिक स्थान, देश के राजनीतिक नेताओं की विदेश में अनुपस्थिति; सत्ता का विभाजन; और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और कानून सम्मत कार्य को लेकर उन्हें चिंता है। पिछले संवैधानिक परिवर्तनों और एक बहुदलीय लोकतांत्रिक स्थिति मजबूत करने के मद्देनजर रिपोर्ट में कुछ कार्रवाइर्यं के महत्व को रेखांकित किया गया है, जिसमें एक समावेशी और समयबद्ध राजनीतिक संवाद, हिरासत में लिए गए राजनीतिक नेताओं की रिहाई और राजनीतिक संवाद में उनकी पूर्ण भागीदारी और 2018 के चुनाव शामिल है।

20 अप्रैल को सीएमएजी ने इन मुद्दों पर चर्चा की। सीएमएजी ने मालदीव की स्थिति को उसके औपचारिक एजेंडे में शामिल नहीं किया; बल्कि सभी पार्टियों के साथ बातचीत और जेल में बंद विपक्षी नेताओं की रिहाई के मामले में सीमित प्रगति पर गंभीर चिंता जाहिर की। सितंबर 2016 तक सीएमएजी ने "स्पष्ट, औसत दर्जे की प्रगति" का आह्वान किया, जब वह "प्रगति का आकलन, छानबीन करेगा और उसीके अनुसार निर्णय लेगा।" मालदीव ने संतोष व्यक्त किया है कि स्थिति को इतना गंभीर नहीं माना गया कि इसे सीएमएजी के औपचारिक एजेंडे पर रखा जाना जरूरी हो।

मौजूदा शासन द्वारा धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों की खुशामद किया जाना भारत के लिए एक अन्य चिंता का सबब है। पूर्व बाहुबली, राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम ने जनता पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए 1997 में मालदीव को इस्लामिक गणराज्य घोषित किया। लोकतंत्र, समानता और उदारवादी विचारधारा का मुकाबला करने के लिए रूढ़िवादियों, मस्जिदों और धर्मों को संगठित किया गया।

मौजूदा जोखिम भरी नीति के बाद, वर्तमान मालदीव शासन सऊदी अरब के साथ मिल कर धार्मिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, यहां तक कि मालदीवियों के बीच प्रचलित सहिष्णु इस्लाम पर जहरीले वहाबी प्रभाव का दरवाजे खोला जा रहा है। राष्ट्रपति यामीन ने पिछले दो वर्षों में तीन बार सऊदी अरब का दौरा किया है और माले में एक सऊदी दूतावास खोला गया है। मालदीव में इस्लामिक मामलों का मंत्रालय आक्रामक तरीके से मालदीव इस्लाम के वहाबीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। पहले से ही, देश में इस्लाम के प्रतीक स्कल कैप, हिजाब के का दिखाई पड़ना आम हो गया है।

मालदीव के नीति नियंताओं को निर्णय लेने के लिए पर्यटकों की खुली जीवन शैली के साथ सरकार समर्थित रूढ़िवादी वर्ग कैसे पेश आएगा। मालदीव के जीडीपी में पर्यटन का योगदान 30% से अधिक है और 2015 में 350 मिलियन की आबादी वाले इस देश में 3 मिलियन से अधिक विदेशी पर्यटकों ने दौरा किया!

मालदीव के कट्टरपंथीकरण पर भारत को चौकस नजर रखने की आवश्यकता होगी; क्योंकि इसकी लहरों को केरल में महसूस किया जाएगा; जो कि यहां की पुरानी सांस्कृतिक और लोगों का मालदीव के

साथ जुड़ाव रहा है। 40 से अधिक मालदीव के युवाओं के सीरिया / इराक में आईएसआईएस के साथ काम करने की खबर है।

इसलिए एवाईएजी की संक्षिप्त यात्रा को मालदीव द्वारा भारत के साथ अपने संबंधों में सुधार की एक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। दोनों पड़ोसियों के बीच यह कुछ खुलकर बातचीत करने और कूटनीति का समय है। मालदीव को भारत की रेड लाइन्स के बारे में चीन और धार्मिक कट्टरवाद दोनों से अवगत कराने की आवश्यकता है। मालदीव को यह समझने की आवश्यकता है कि उसे भारत को उकसाने से बचना चाहिए और अपने विशाल नजदीकी पड़ोसी की सुरक्षा और रणनीतिक हितों की पूरी तरह से सराहना और समायोजन करना चाहिए।

भारत को अपनी ओर से मालदीव को आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि सिद्धांतया हम लोकतंत्र और उदार राजनीति का समर्थन करते हैं, हम किसी देश के आंतरिक राजनीतिक संघर्ष में भाग नहीं लेंगे।

विश्लेषण का अंतिम लव्वोलुआब है कि क्षेत्र में कुशलता, सुरक्षा और स्थिरता का मुद्दा सर्वोपरि है और इस क्षेत्र के देशों द्वारा ही इसे बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग के लिए कार्य योजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर महत्वपूर्ण है।

***

*लेखक कोरिया गणराज्य के पूर्व भारतीय राजदूत हैं।